**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**27.07.2018 के**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1253 का उत्‍तर**

**रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई**

**1253. श्री माजीद मेमनः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि कंपनियों ने डी, ई तथा एफ श्रेणियों के अंतर्गत 7700 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा प्रदान करने में अधिक रुचि नहीं दिखाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे वाई-फाई स्थलों से विज्ञापन की बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 170 बिलियन तक अधिक हो सकता है; और

(ग) इन सभी रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सेवाओं की आपूर्ति, संस्थापन, जांच, शुरुआत, संचालन तथा रख-रखाव हेतु निजी फर्म को आकर्षित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. : रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलटेल द्वारा डी, ई और एफ कोटि के स्‍टेशनों पर वाई-फाई की व्‍यवस्‍था के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने की संभावना हैं।
2. : इस कथन की पुष्टि के लिए ऐसा कोई डाटा/योजना उपलब्‍ध नहीं है।
3. : डी, ई और एफ स्‍टेशनों की कोटि के लिए, निविदा प्रकियाधीन है और इन्‍हें वायबिलिटी गैप वित्‍त व्‍यवस्‍था माध्‍यम के आधार पर आमंत्रित किए जाने की संभावना है।

वाई-फाई परियोजना को कॉर्पोरेट सोशल रिस्‍पांसबिलिटी (सीएसआर) से समर्थन प्रदान करने के लिए उद्योगों को प्रोत्‍साहित करने हेतु उनके साथ चर्चा की जा रही है।

डी, ई और एफ कोटि के स्‍टेशनों पर वाई-फाई सुविधा की व्‍यवस्‍था के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत धनराशि की व्‍यवस्‍था करने के लिए दूर संचार विभाग के साथ भी संपर्क किया गया है।

\*\*\*\*\*\*